

ducers and Production Assistants. The system of engagement of Stringers is also under examination with a view to streamlining it.

**बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड को मिला कर  
नये राज्य की स्थापना**

4142. श्री सुखेन्द्र सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पुराना विन्ध्य प्रदेश, जिसमें बुन्देलखंड और बघेलखण्ड का पुराना क्षेत्र शामिल है, देश में पिछड़ा क्षेत्र है; और

(ख) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत इस पिछड़े क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जायेगा और उक्त क्षेत्र के विकास और मज्जि के लिये नई योजनाएं और विकास कार्य आरम्भ किये जायेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : क और (ख). जी हां, श्रीमान। मध्य प्रदेश में बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड के कुछ भाग पिछड़े क्षेत्र हैं और वहाँ अनेक जिलों को आर्थिक रिआयत के लिए योग्य मानते हुए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से योजना की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना है और सरकार यह नहीं समझती कि ऐसे क्षेत्रों का एक पृथक राज्य बनाने से उनके पिछड़ेपन की समस्या का समाधान हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना 1977-78 के प्रारूप में बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड क्षेत्र में शुरू करने के लिए कुछ सिंचाई योजनाएं, बड़ी तथा मध्यम दोनों, और कुछ विद्युत परियोजनाएं निहित हैं।

**Film 'Kissa Kursi Ka'**

4143. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what was the agency or the particular officer who ruled that the Hindi film entitled 'KISSA KURSI KA' could not be released to public, the reasons why such a decision was taken;

(b) who was producer and director of this film, who were its financiers, whether any assistance to it was sought from Film Finance Corporation; and

(c) what was the criterion of considering this film as not worth release to public, whether Government would release it if its copy was made available now?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (c). The film KISSA KURSI KA was examined by the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Cinematograph Act, 1952 and it was decided that the film should not be given a censor certificate for public exhibition, on the grounds that the film was against the interests of the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, and was likely to incite the commission of offences against the established laws of the country. These powers were exercised by the then Joint Secretary (Information) in the Ministry of Information and Broadcasting, Incharge of the Film Wing, with the approval of the then Minister for Information and Broadcasting.

With regard to permitting the release of this film if a copy now becomes available, the Central Government, having already refused a